GLOBAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES UGC APPROVED ISSN: - 2348-0459
www.gjms.co.in
Volume-6, Issue-8, July 2017 Impact Factor: 3.987

Paper ID: UGC 48846-875

GOOD GOVERNANCE PROBLEM AND CHALLENGES IN INDIA (IN THE CONTEXT OF GLOBAL DEVELOPMENT)

Madan Murari Prajapati
Research Scholar Economics Research Center (R.D.V.V.) Jabalpur M.P.

सारांश: शासन आदिम युग की कवीबाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता विकास क्रम में अलग–अलग विशिष्ट रूपों में शासन प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होती आई है। इस विकास क्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोक कल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। स्वतंत्रता के पूर्व महात्मा गांधी के सुशासन की अवधारणा में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अनिवार्य था। परंतु 1990 के दशक के प्रारंभ में सुशासन का विचार एक ऐसे महावरे में बदल चुका था जो एशिया और अफ्रीका के ऋणग्रस्त देशों के लिए दानदाता देश ' शर्तों के रूप में इस्तेमाल करते थे। विश्व के अनेक भागों में इसे सामाजिक अशांति और राजनीतिक उथल–पुथल के लिए दोषी ठहराया जाता था। दमन और ' शक्ति के दुरूपयोग से मुक्त सुशासन की अवधारणा आज आकर्षण का विषय बनी हुई है। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के जटिल संबंधों के बीच सहभागी विकास निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, योजनाओं के क्रियान्वयन और अंर्तसम्बंधों के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि यह सही है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से समाज के एक बड़े वर्ग के दूर रहने से प्रशासन गैर–जिम्मेदार हो जाता है और शोषणकारी प्रणाली को जन्म देता है। सुशासन एक गतिशील धारणा है यह केवल सरकार के लिए चिंता का विषय नही होना चाहिए। समाज और सरकार के बीच निरंतर और निर्णायक चर्चा अति आवश्यक है ताकि सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

शब्दकोश :लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, क्रियान्वयन

प्रस्तावना एक समय था जब लोकतंत्र की यह अवधारणा ही लोगों को खुश करने के लिए काफी थी कि यह "जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रशासन हैं किंतु पिछले कुछ दशकों में प्रशासन की इस व्यवस्था में भी कई खामियां स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी थी। इसके बाद लोकतंत्र के पशासनिक व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया तेज होने लगी । अब लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन के प्रति सरकार की जवाबदेही और इसमें पारदर्शिता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सक्षम और प्रभावकारी हो सकी। इसी बेहतर प्रशासन व्यवस्था को लोगों ने सुशासन नाम दिया। सुशासन का सम्बंध जवाबदेही राजनीतिक नेतृत्व, प्रखर नीति निर्माताओं और कार्यकुशल लोक सेवकों से है। सशक्त नागरिक समाज के साथ–साथ स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्याय पालिका सुशासन की पूर्ण ' शर्त है।

विश्व बैंक ने भी सुशासन की एक आर्थिक परिभाषा गढ़ी थी जिसका संदर्भ 1991 में उदारीकरण के दौर से ही देखा जा सकता है "सुशासन एक लोकतांत्रिक प्रवर्धित अवधारणा है जो ' शासन को अधिक खुला, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। जिसमें IT, RTI, डिजिटल इंडिया आदि का अधिक महत्व है, मानव अधिकार सहभागी विकास और परदर्शी लोकतांत्रिक ' शासन आदि सुशासन की सीमा में आते हैं।

Objectives

शोध पत्र में सुशासन के सम्बंध में UNO द्वारा जारी सुशासन के Objective जो इस प्रकार हैः–

1. कानून का शासन Rule of Law द्वारा
2. समानता एवं समावेशन सम्बंध में (Equility and Inclusiveness) द्वारा
3. भागीदारी (PARTICIPATION)
4. उत्तरदायित्व (Responsiveness)
5. लोकतांत्रिक (Consensus)
6. प्रभावशीलता व दक्षता (Effectiveness and Efficiency)
7. पारदर्शिता (Transparency)
9. जिम्मेदारी (Accountability)
10. निष्पक्ष आकलन

उपरोक्त OBJECTIVES_को ध्यान में रखते हुए विश्व के परिपेक्ष में भारत के सुशासन की चुनोतियों का अध्ययन किया गया है।

Data Base and Research Mathodology

शोध पत्र में द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है जिन्हें शासकीय वेबसाईटों एवं ' शासकीय रिपोर्टों से संकलित किया गया है ' शोध में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015–16 भारतीय जनगणना 2011 के अलावा विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित समंकों का उपयोग कर भारत में सुशासन के

जिम्मेदारियों के संबंध में समंकों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्षों को विवेचित किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

- एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2014 में गरीबी का आधार 1. 51 डालर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आप को माना है जिसके अनुसार देश की 58.40 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। यह आधार वास्तविकता के अधिक करीब प्रतीत हो रही है, क्योंकि Globe Hunger index 2016 के अनुसार भूखे लोगों के मामले में भारत 110 देशों में 97वें नंबर पर था। पाकिस्तान के अलावा सभी सार्क देश एवं ब्रिक्स देश भारत से बेहतर स्थिति में थे जैसेः–

देश	भूखे लोगों के मामले में विश्व में रैंक	देश	भूखे लोगों के मामले में विश्व में स्थान
ब्राजील	16	नेपाल	72
रूस	24	श्रीलंका	84
चीन	29	बांग्लादेश	90
अफ्रीका	51		

- गरीबी निवारण की योजनाओं के मामले में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है विश्व के किसी भी देश से अधिक यहां योजनाऐं संचालित हैं किन्तु क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं लोगों की सहभागिता के अभाव के कारण अधिकांश योजनाओं की जानकारी तक गरीबों तक को नहीं होती लाभ प्राप्त करना तो दूर की कोंड़ी हैं जबकि अन्य देशों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से वहां गरीबी निवरण तेजी से हुआ हे जैसेः–

देश	1992 में गरीबी : में	2016 में गरीबी : में
चीन	42	11
वर्मा	62.7	14
भारत	30.1	26.1

स्पष्ट है कि वर्ष 1992 से लेकर 2016 तक भारत में मात्र 4 फीसदी लोगों का ही गरीबी से निजात मिल सकी है जिसका कारण योजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन कि विभिन्न स्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार है। यद्यपि विश्व के 60 प्रतिशत देशों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। जी–20 समूह के आधे से अधिक देश भ्रष्टाचार की गंभीरता से ग्रसित हैं किन्तु भारत की स्थिति बेहद भ्रष्टाचार वाले देश की है जैसेः–

Corroption Perception Index 2015

रैंक	देश	भ्र" टाचार सूचकांक
1	डेनमार्क	91
2	फिनलैण्ड	90
3	स्वीडन	89
76	ब्राजील, भारत	38
83	चीन, श्रीलंका	37
117	पाकिस्तान	30

- भ्रष्टाचार के कारण ही योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता और गरीब अधिक गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर होता चला जा रहा है। अभी हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 58 प्रतिशत संपत्ति है और एक प्रतिशत में ललित मोदी, विजय माल्या जैसे अन्य भ्रष्टाचारी लोग भी ' शामिल हैं । बिना भ्रष्टाचार पर रोक लगाये सुशासन की कल्पना मात्र की जा सकती है।
- विश्व के विभिन्न देशों में विनियामकीय गुणवक्ता एवं दक्षता के आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि किस देश में व्यवसाय स्थापित करना एवं परिचालन करना कितना आसान एवं कठिन है। भारत में कागजी प्रक्रिया की जटिलता, समय की अधिकता, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, अधोसरंचना के अभाव के कारण बढ़ती लागत आदि के कारण देश में व्यवसाय स्थापित करना एवं संचालित करना बहुत कठिन है यही कारण है कि विश्व बैंक की Doing Business Report 2016के अनुसार भारत की स्थिति बेहद निराशा जनक है विदेशी निवेश कम होने का भी यही एक कारण है।

Daing Business Report : 2016

देश	रैंक	मान
सिंगापुर	1	87.34
न्यूजीलैण्ड	2	86.79
रूस	51	70.99
द.अफ्रीका	73	64.89
चीन	84	62.93
नेपाल	99	60.41
श्रीलंका	107	58.96
ब्राजील	116	57.67
भारत	130	54.68

- देश में राजनैतिक वातावरण, व्यवसायिक वातावरण, मानवीय पूंजी एवं अनुसंधान, अधोसंरचना, बाजार परि" करण एवं सृजनात्मका के आधार पर जारी Global innovation Index: 2015 के अनुसार भी भारत की स्थिति बेहद निम्न है।

देश	रैंक	मान
स्विट्जरलैंड	1	68.30
यू.के	2	62.42
चीन	29	47.47
रूस	48	39.32
द.अफ्रीका	60	37.45
ब्राजील	70	34.95
भारत	81	31.74

- इक्कीसवीं ' शताब्दी में प्रतिभा को अमानवीयकरण, प्रतिस्पर्धात्मक एवं संवृद्धि को आपस में जोड़ने वाला सर्वाधिक प्रमुख कारण माना जा रहा है किस प्रकार कोई देश अपनी मानव पूंजी को विकसित करता है और उत्पादक कार्यों में लगाता है तथा समय–समय पर इसका मूल्यांकन भी करता है आदि उस देश के सुशासन के अंतर्गत आता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित मानव पूजीं सूचकांक 2015 में भी भारत की स्थिति बदतर है:–

देश	रैंक	मान
फिनलैण्ड	1	85
नार्वे	2	83
रूस	26	77
चीन	64	64.47
ब्राजील	66	61.17
द.अफ्रीका	92	60.50
भारत	100	57.62

- पिछले तीन वर्षों से हमारी अर्थ–व्यवस्था संकट में है। विकास दर लगातार गिर रही है मंहगाई बढती जा रही है और रूपया टूट रहा है इन सभी समस्याओं की जड़ में कुशासन ही दिखाई देता है। हमारे उद्यमियों को भारी मात्रा में घूस देनी पड़ती है अतः माल मंहगा हो जाता है जबकि दूसरे देश में लागत कम आती है, निर्यात कम होने के कारण डॉलर कम मात्रा में मिलते हैं आयात ज्यादा होने के कारण मंहगा हो जाता है। यही कारण है कि विदेशी सस्ता माल हमारे घरेलू बाजार में ही हमारे माल को चलन से बाहर कर रहा है

और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो देश सुशासित होगा वही जीतेगा।

- भारत में सुशासन को तीव्रता देने वाले कई कृत्य जैसे मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया सहित कौशल विकास जैसी महत्वकांक्षी परियोजनाओं से युक्त विशिष्टताओं को देखे तो सुशासन की गणना में सरकार आगे जाती हुई दिखाई देती है पर क्या बिना स्क्लि डेवलपमेंट के काई काम पूरे होंगे संदेह है। हालांकि सरकार इस बात को मानती है कि युवाओं को हुनर बंद बनाकर न केवल विकास को संभव किया जा सकता है बल्कि नियंत्रण स्तर पर स्किल निर्यात को भी संभव किया जा सकता है। बिना स्किल डेवलपमेंट के सुशासन को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है। क्योंकि भारत में ऐसी संस्थाओं की कमी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन में पांच लाख, जर्मनी, आस्ट्रेलिया में एक–एक लाख कौशल विकास से जुड़ो संस्थाऐं हैं किन्तु भारत में ऐसी संस्थाऐं मात्र 15 हजार ही हैं। इतना ही नहीं चीन में तीन हजार से ज्यादा कौशल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है भारत यहां भी काफी सीमित है। चीन अपनी ळण्क्ण्च्च का 2.5 प्रतिशत व्यवसायिक शिक्षा पर खर्च करता है। भारत में यही खर्च G.D.P. का मात्र 0.1 फीसदी है।
- सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति के आयोग जैसे थिंक टैंक को निर्मित करने के पीछे उद्देश्य विकास और सुशासन को प्रासंगिक बनाना ही रहा है। हाल के दशकों में विभिन्न देशों की प्रशासनिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरण नीतियों पर भी नियंत्रित स्तर पर की जा रही चिंता इसकी एक बानगी है। सुशासन के लिये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी है। यह तय माना जा रहा है कि सुशासन किसी भी देश की विकास कुंजी है और यह तभी संभव है जब जवाबदेही को व्यापक स्थान मिले। डिजिटल गवर्नेंस को भारत में नवीन लोक प्रबंधन के प्रभावशाली उपकरण के रूप में संचालित किया जा रहा है। देखा जाये तो सुशासन के युग में प्रवेश हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है पर आधुनिक परिपेक्ष में इसका पोषण आशा के अनुरूप होता दिखाई देता है। अंततः यह सही है कि जहां विकास के ' शुरूवाती दौर में प्रौद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के साथ पश्चिमीकरण का महत्व होता था वहीं इक्कीसवीं सदी के दौर में बकायदा सुशासन को बारीकी से प्रासंगिक बनाया जा रहा है।

Conclusion

सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समय पर क्रियान्वयन ही सुशासन है। पूर्ववर्ती सरकारों की कुव्यवस्था के चलते सुशासन दिवस का आयोजन प्रतीक के स्तर पर ही सही वक्त की जरूरत है। हालांकि इस कलयुगी व्यवस्था में सुशासन दिवस मनान के बाद किसी रामराज्य की कल्पना करना तो बेईमानी होगा, लेकिन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद तो की ही जा सकती है। वैसे भी इस मुल्क में अच्छी योजनाऐं क्रियान्वयन के स्तर पर ही आकर दम तोड़ती रही हैं। योजनाओं का पूरा लाभ आम आदमी को अब तक नहीं मिल सका है। इसके कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिज्ञों और अफसरों का भृष्ट गठजोड़, जनता का जागरूक न हाना, मीडिया की संवेदनहीनता। इन्हीं सबके कारण भारत और इंडिया के बीच बड़ा फर्क आज भी कायम है यही वजह है कि आबादी का बड़ा तबका आज भी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है दूसरी तरफ हमारे नीति निर्माता 5 रूपये से लेकर 22 रूपये में दिन बिताने के कुतर्क देते रहते हैं। यह उसी मुल्क की तस्वीर है जहां एक तरफ हर दो घण्टें मे तीन किसान आत्म हत्या करते हैं दूसरी तरफ लाखों, करोड़ों के घोटालों को हमारे माननीय समान घटना करार देते हैं। इसी राजनीति के चलते इस मुल्क में सुशासन का इंतजार बहुत लंबा है।

राजनीति में बढ़ता धन बल, विचारधाराओं का लोप होना और भ्रष्टाचार सुशासन के सामने सबसे बड़ी बाधाऐं हैं। वैसे आम आदमी कार्य पालिका के स्तर पर ही हर रोज सुशासन खोजता है। दरअसल तहसील और जिले के सरकारी दफ्तारों में व्याप्त भृष्टाचार अधिकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी औचित्यहीन नियम कानून से निपटना आज भी बड़ी चुनौती है। सवाल यह भी है कि आम आदमी भी जवाबदेही के किस पायदान पर खड़ा है? हम खुद कितने जवाबदेह हैं? जाहिर हे सुशासन लाने के संदर्भ में समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा।

आज भले ही सुशासन की बात की जा रही हो एवं इस दिशा में कई प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि जहां लोगों को सही समय में न्याय नहीं मिल पाता वहां सुशासन कैसे हो सकता है? कानून की दृष्टि में सभी समान हैं किन्तु आज कल हर जगह देखने में आता है नेता और दबंग नागरिकों पर अपनी दादागिरी दिखाने एवं लूट पात करने से बाज नहीं आते, जब तक इस प्रकार का अन्याय खत्म नहीं होगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि सुशासन स्थापित हो चुका है।

गवर्नेस का ग्लोबलाईजेशन हो चुका है ऐसे में हमारे पास अपनी ' ाासन प्रणाली को ग्लोबल स्टैण्डर्ड पर सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं है यद्यपि विगत वर्षों से सरकार ने सुशासन के लिये RTI, लोक सेवा गारंटी, ई–प्रशासन, महिला शसक्तीकरण एवं स्व. रोजगार की योजनाओं जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सुशासन की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु अभी भी सार्थक परिणाम अपेक्षित है।

संदर्भग्रंथ

1. M.P. Singh and Saxena, 2008 (India Politics contempary and cocern) PP: 47-48
2. Amarty Sen, 2006, Indentity and Violence
3. Prajapati M uoacj 2016 सतत् विकास प्रासंगिकता में भारत की सामाजिक अवसंरचना की दशा एवं दिशा Global Journal of Engineering, Science & S.S. Studies: Volum- 02 , ISSN no. 2394 - 3048 Website: www.gress.co.in PP-96-103
3. सिंह सुशील, राष्ट्रीय सहारा दिसम्बर 2015
4. दीक्षित अनुराग 26 दिसम्बर 2014 जागरण
5. झुनझुनवाला भरत 1 जनवरी 2014 नवभारत टाइम्स
6. Hhps:// hi.m.wikipedia.org.
7. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक (भारतीय अर्थव्यवस्था) : 2016 PP: 328.330
8. भारतीय अर्थव्यवस्था : (शिवकुमार ओझा): 2015 वृतीय संस्करण
9. आर्थिक परिदृश्य : दृष्टि पब्लिकेशन 2016
10. बाल्मीकि प्रसाद सिंहः जनवरी 2013, योजना, PP: 01 ISSN. 0971-8397

*****